हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 136 देहरादून, बुधवार, 16 नवंबर, 2022 मूल्य : एक रुपया पृष्ठ : 08

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल 3

आपदा प्रबंधन एवं भूकम्परोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान से सहयोग लिया जाए : मुख्यमंत्री

उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग जापान में

■ फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से आयोजित संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर एवं जापान और उत्तराखण्ड के बीच पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जापानी प्रतिनिधिमण्डल का जापानी भाषा से शुरूआत कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड भूकम्प एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। आपदा प्रबंधन एवं भूकम्परोधी तकनीक के क्षेत्र में जापान राज्य को क्या सहयोग दे सकता है, इस दिशा में प्रयास किये जाएं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के लिए जापान से सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन, कृषि, हॉर्टीकल्चर के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास भी किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों की वैल्यू एडिशन कर मार्केटिंग में जापान से किस प्रकार सहयोग लिया जा सकता है, इस ओर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के स्थानीय कल्चर एवं सांस्कृतिक विरासत से संबंधित जानकारी एवं अन्य अध्ययन के लिए जापान से कोई भी प्रतिनिधिमंडल उत्तराखण्ड आना चाहते हैं, तो उनका देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत है। राज्य द्वारा इसके लिए हर संभव सहयोग दिया जायेगा।

■ जापानी डेलिगेशन का जापानी भाषा में बोलकर मुख्यमंत्री ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड योग, आयुष, वैलनेस टूररिज्म के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। इन क्षेत्रों में जापान को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, वह दी जायेगी।

इस अवसर पर सांसद एवं फिक्की फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन्स के अध्यक्ष राजीव प्रताप रूडी, भारत जापान दूतावास के उप प्रमुख कुनिहिको कावाजू, फिक्की के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मनीष सिंघल, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा आदि उपस्थित थे।

इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के कार्य में तेजी लाएं: डॉ. आर. राजेश कुमार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवंबर। देहरादून स्थित सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव (प्रभारी) डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज (ई.सी.आर.पी.) व प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के कार्यों मे तेजी लाने व जल्द पूर्ण करने को लेकर संबंधित विभागों, अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक ली गई।बैठक में ई.सी.आर.पी. के अंतर्गत निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक की समीक्षा की गई। जिसमें 07 प्रस्तावों में से 05 के आगणन पर विभागीय कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है एवं शेष 02 जनपदों की डी.पी.आर. ना आने पर प्रभारी सचिव द्वारा नाराजगी व्यक्त कर कार्यदायी संस्था को जल्द ही शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए।

समीक्षा बैठक में राज्य में ई.सी.आर.पी. के अन्तर्गत चिन्हित अस्पतालों में आई.सी.यू बेड जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गये। राज्य के 45 अस्पतालों में से 37 में मेडिकल ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन व 08 में शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी ब्लाकों में ब्लॉक पब्लिक हैल्थ यूनिट जिसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में लैब एवं हेल्थ मॉनिटरिंग की यूनिट स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री अटल आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2020-26 तक चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत अनुमोदित सी.सी.बी. ब्लॉक की डीपीआर भी शासन को अनुमोदित कर दी गई है।बैठक में स्वास्थ्य निदेशक डॉ. विनीता शाह, अनु सचिव जसविंदर कौर, कार्यक्रम अधिकारी-ईसीआरपी डॉ. अभय कुमार, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी देवेंद्र नैलवाल, डॉ. बी.के. शुक्ला, अधिशासी अभियंता बी.डी. पांडे, सिचाई विभाग, ब्रिडकुल, आदि अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।

स्वर्ण पदक विजेता मानसी नेगी और एथलीट सूरज पंवार को 2-2 लाख की राशि देगी धामी सरकार

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवंबर। मुख्यमंत्री ने दोनों एथिलीट को सीएम कोष से दो-दो लाख रूपये की धनराशि देने की घोषणा की। जबकि खेल विभाग की नियमावली के मानकों के अनुसार 1-1 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। इस प्रकार कुल 3-3 लाख रूपये की राशि दोनों एथलीट को मिलेगी।देहरादून , 16 नवम्बर, मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट को आगामी खेलों की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगे भी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण आदि के लिए हर संभव मदद दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने दोनों एथलीट के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इस अवसर पर उप क्रीडा अधिकारी एवं इन दोनों खिलाड़ियों के कोच अनूप बिष्ट एवं एथलीट मनीष बिष्ट मौजूद थे।

काम की बात : घर बैठे खोलें एसबीआई के साथ एफडी अकाउंट, जानिए पूरी प्रक्रिया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवंबर , अगर आप घर बैठे फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बिना कहीं जाए आसानी से एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. क्योंकि एसबीआई ग्राहकों को अपने साथ घर बैठे फिक्स्ड डिपॉजिट करने की सुविधा प्रदान करता है. फिक्स्ड डिपॉजिट हमेशा से लोगों के इंवेस्टमेंट के लिए एक आसान और सुरक्षित ऑप्शन रहा है. फिक्स्ड डिपॉजिट इंवेस्टमेंट पर एक तय ब्याज दर पर मैच्योरिटी की तारीख पर गारंटीड राशि देता है. Fixed Deposit की सुविधा बैंक और एनबीएफसी (Non-Banking Financial Company) देती हैं.

एफडी में आपके मूलधन के नुकसान का कोई रिस्क नहीं रहता है. साथ ही एफडी में इंवेस्टमेंट करने पर रिटर्न का मिलना निश्चित रहता है. आप एफडी को आसानी से रिन्यू करवा सकते है. फिक्स्ड डिपॉजिट में इंवेस्टमेंट का सीनियर सिटीजन को अच्छा फायदा मिलता है. इसमें निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को हाई ब्याज दर मिलती है. अगर आप एसबीआई के साथ एफडी करना चाहते हैं तो आसानी से घर बैठे ऑनलाइन एफडी अकाउंट खोल सकते हैं.

घर बैठे ऐसे खोलें ऑनलाइन अकाउंट

एफडी के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए SBI की ऑफिशियल वेबसाइट https://sbi.co.in/ पर जाएं.

यहां अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर नेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा.

फिर होम पेज ऑप्शन में जाकर डिपॉजिट स्कीम ऑप्शन को चुनें.

इसके बाद एफडी का ऑप्शन सिलेक्ट करके फिर ई-एफडी का चयन करें.

इसके बाद आपको जिस तरह का अकाउंट ओपन करना है उसे सिलेक्ट करें. और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करें.

फिर उस खाते को सिलेक्ट करें जिससे पैसे कट कर फिक्स्ड डिपॉजिट एकाउंट में जमा होंगे.

इसके बाद एफडी की प्रिंसिपल वैल्यू भर दें.

अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें.

फिर एफडी की मैच्योरिटी डेट का सिलेक्शन करें.

अब सभी टर्म्स एंड कंडीशन्स को सिलेक्ट करें.

आखिर में सबमिट का बटन क्लिक करें, आपका ऑनलाइन एफडी अकाउंट खुल जाएगा.

मुगलकाल के तलाक और निकाह के वो नियम जो आपको चौंका देंगे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवंबर , मुगलों के उस दौर में महिलाओं के पास खुले तलाक का विकल्प था. तलाक को लेकर महिलाएं जागरूक भी थीं और अपनी बात खुलकर सामने भी रखती थीं. पढ़ें उस दौर में तलाक और निकाह को लेकर क्या नियम थे...

पिछले कुछ सालों में तीन तलाक का मुद्दा चर्चा में रहा. मुगलों के दौर में भी यह चर्चा की वजह बना था. मुगल बादशाह जहांगीर के काल में तलाक के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया गया था. इसका जिक्र मुगलकाल के ऐतिहासिक दस्तावेज 'मजलिस-ए-जहांगीरी' में किया गया है. 20 जून 1611 को जहांगीर ने तलाक को लेकर घोषणा की थी कि अगर कोई मुस्लिम शख्स बीवी से बिना किसी बड़ी वजह के तलाक लेता है तो उसे अवैध करार दिया जाएगा. उनकी उस घोषणा पर शाही काजी ने भी मुहर लगाई थी.

यह वो दौर था जब शादी का वादा करने और तलाक देने में इंसान की जुबान को ही सब कुछ माना जाता था. गरीबों में शादियां कैसे टूट जाती थीं, इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है जो इतिहास में दर्ज हुए, लेकिन ऐसे मामलों में महिलाओं की भी सुनवाई की जाती थी. उनकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता था.

महिलाओं के पास था 'खुले तलाक' का विकल्प

मुगलों के उस दौर में महिलाओं के पास खुले तलाक का विकल्प था. इसे उस दौर के कुछ मामलों से समझा जा सकता है. 1628 में एक मुस्लिम शख्स ने शादी को खत्म करने के लिए पत्नी से 70 महमूदिस सिक्के लेकर रजामंदी की बात कही. वहीं, एक दूसरे मामले में फत बानू अपने पति चिश्त मुहम्मद को काजी के सामने लेकर आई और कहा, अगर मेरा पति दोबारा शराब या ताड़ी पीता है तो उससे पति का अधिकार छीना जाए. और ऐसा ही होता भी था. उस दौर के मामले बताते हैं कि महिलाएं किस कदर तलाक को लेकर जागरूक थीं और अपनी बात काजी के सामने रखने में कतराती नहीं थीं.

5 फरवरी 1612 में मोहम्मद जियू नाम के शख्स ने काजी के सामने पत्नी को रोजाना एक तांबे का सिक्का, साल में दो साड़ी और दो कुर्ती देने की बात कही.

कहा, ऐसा न होने पर वो क्षतिपूर्ति देगा. करीब 7 साल बाद दंपति काजी के सामने दोबारा पेश हुआ. शौहर ने काजी से शिकायत करते हुए कहा कि मेरी पत्नी ने घर छोड़ दिया है. मरियम ने अपना पक्ष रखते हुए वो दस्तावेज दिखाया जिसमें जियू ने हस्ताक्षर करते हुए लिखा था कि अगर क्षतिपूर्ति भी नहीं दे पाया तो शादी खत्म मानी जाएगी. मरियम का कहना था, पिछले 5 साल से उसने अपने वादे पूरे नहीं किए. इस तरह दोनों की बात सुनने के बाद काजी ने तलाक पर मुहर लगा दी.

शाही परिवार में क्या नियम थे?

उस दौर में शाही परिवार के अपने ही नियम थे और उन्हें कई अधिकार प्राप्त थे. इसका एक उदाहरण शाहजहां के प्रधानमंत्री रहे आसिफ खान से समझा जा सकता है. आसिफ खान की एक बेटी थी, नाम था मिसरी बेगम. उसकी शादी मुगल सल्तनत के एक अधिकारी मिर्ज़ा जरुल्लाह से हुई थी.एक बार मुगल बादशाह मिर्ज़ा जरुल्लाह से नाराज हो गए. बादशाह ने अपना गुस्सा दोनों की शादीशुदा जिंदगी पर उतार दिया. उन्होंने मिर्ज़ा जरुल्लाह और मिसरी बेगम के बीच तलाक कराने का आदेश दे दिया. बादशाह का आदेश होने पर उसे तेजी से अमल में लाया गया.

शादियों को लेकर क्या थे नियम?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उस दौर में निकाह के लिए जो नियम थे वो थोड़े चौंकाते हैं क्योंकि आज की जो स्थिति है उससे काफी उलट थे. ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि निकाह के लिए बने 5 नियमों को मानना पड़ता था. जैसे- एक बीवी के होते हुए शौहर दूसरी शादी नहीं करेगा. वो अपनी बेगम के साथ मारपीट नहीं करेगा. बीवी से लम्बे समय तक दूर नहीं रहेगा और उसके गुजर-बसर का इंतजाम करेगा. इतना ही नहीं, शौहर किसी भी दासी को पत्नी के अधिकार नहीं देगा.

अगर कोई शौहर पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करता है. पहली पत्नी को मारता है और उससे दूरी बनाकर रता है तो शादी को तोड़ा जा सकता है. हालांकि पति गुजर-बसर के लिए रकम दे या नहीं, इसका फैसला लेने का अधिकार महिलाओं के पास होता था. वहीं, लिखित निकाहनामा की परंपरा केवल सम्पन्न परिवार में प्रचलित थीं.इन नियमों का जिक्र औरंगजेब के दौर की किताबों में भी मिलता है जो पुष्टि करते हैं कैसे लम्बे समय तक इनका पालन हुआ है.

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल

सचिव ऊर्जा एवं प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल ने मुख्यमंत्री को सौंपा लाभांश का 20 करोड़ का चेक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम से जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, क्षमता विकास एवं बेहतर कार्य संस्कृति के साथ प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में कार्य करने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के मूल में उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की अवधारणा को भी साकार करने में विद्युत निगमों से सक्रियता से सहयोगी बनना होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम के 22 वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यूजेवीएनएल ने जल विद्युत क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य ही नहीं अपितु देशभर के सरकारी संस्थानों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज्य स्थापना के उपरांत यूजेवीएनएल का गठन उत्तराखण्ड को सही अर्थों में ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए किया गया था। इस सम्बन्ध में यद्यपि यूजेवीएनएल द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं फिर भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियों का हमें सामना करना है। इसके लिये हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे तभी हम उज्ज्वल उत्तराखण्ड के निर्माण में सफल हो सकेंगे तथा ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को पूर्ण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के नैसर्गिक, प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग करना होगा तथा राज्य आर्थिकी के विकास के लिये समेकित प्रयास करने होंगे।

- पिटकुल के प्रबंध निदेशक ने भी मुख्यमंत्री को सौंपा 5 करोड़ के लाभांश का चेक
- प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के हों प्रयास : मुख्यमंत्री।

इस अवसर पर सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम तथा प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने निगम के लाभांश का 20 करोड़ तथा प्रबंध निदेश पिटकुल पी.सी ध्यानी ने 5 करोड़ का लाभांश का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम को अपनी बेहतर कार्यसंस्कृति और कुशल प्रबन्धन के बल पर इसी प्रकार ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिये प्रयासरत रहना होगा। राज्य निर्माण के समय ऊर्जा क्षेत्र को हमारी आर्थिकी का मूल आधार माना गया था, परंतु यह लक्ष्य अभी तक पूर्णरूपेण सफल नहीं हो पाया है। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर यह विचार करें कि इस दिशा में कैसे तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है। हमें इसके लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र की विकास योजनाओं को समय पर पूर्ण करने में हमें केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। इसका उदाहरण लखवाड़ बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना एवं जमरानी बांध परियोजना है जिसमें तेजी से कार्य किया जा रहा है।

राज्य सरकार जीरो पेंडेसी वर्क कल्चर पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिये हर क्षेत्र में सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि के मूल मंत्र के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। हमें अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी ऊर्जा के साथ निरंतर कार्य करते हुए करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है और हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर इसे पूर्ण करने की दिशा में कार्यरत है।हमारा संकल्प है कि 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा तब तक हर क्षेत्र में हमारा राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। लक्ष्य को पूर्ण करने एवं उत्तराखंड को विकसित, सक्षम व आदर्श राज्य बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन आठ सालों में एक समृद्ध, शक्तिशाली तथा समरस भारत के साथ ही दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बना है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभाओं की पहचान के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार हो रही है। आज का भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत है। पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता का ही प्रभाव है कि हमारे देश की प्रतिभाये देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश की पहचान बन रही है।

सचिव ऊर्जा आर. मीनाक्षी सुंदरम तथा प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल संदीप सिंघल द्वारा निगम के कार्यकलापों की जानकारी दी गयी। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी, प्रबंध निदेशक यूपीसीएल श्री अनिल यादव सहित अन्य अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

20 लाख रुपए आंतरिक मार्ग, पथ प्रकाश, कैमरा देने की घोषणा : प्रेमचंद अग्रवाल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ऋषिकेश 15 नवंबर। हरिपुरकलां में क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल का मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन और जिलाध्यक्ष रविन्द्र राणा का स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं से मंत्री डॉ अग्रवाल को अवगत कराया।

इस दौरान मंत्री डॉ अग्रवाल ने विधायक निधि से 20 लाख रुपए आंतरिक मार्ग, पथ प्रकाश, कैमरा देने की घोषणा भी की। इस दौरान सीवर, बिजली विभाग की समस्या का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

इस मौके पर थानाध्यक्ष रायवाला को नशा के खिलाफ अभियान चलाने तथा रोजाना रात्रि गश्त करने के भी निर्देश दिए। मंगलवार को हरिपुरकलां में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि हरिपुरकलां से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, यहाँ का आशीर्वाद मुझे पिछले चार बार से मिल रहा है। आप ही कि बदौलत मंत्री पद तक पहुंचे हैं। डॉ अग्रवाल ने कहा कि राज्य को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल रहा है। राज्य सरकार पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विकास कार्य के लिए दृढ़ संकल्पित है। कहा कि हमारी सरकार ने राज्य को 2025 तक देश का अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा में कभी भी विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।

यहाँ के विकास कार्यो के लिए वचनबद्ध हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर कार्य करती है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य की युवा पुष्कर सिंह धामी की सरकार सराहनीय कार्य कर रही है।

पराली को बिना जलाए ही सुपर सीडर के माध्यम से गेहूं की बुवाई की जाए : डीएम यूएस नगर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

किच्छा, 15 नवम्बर । जिलाधिकारी युगल किशोर पंत की उपस्थिति में किच्छा के ग्राम किशनपुर में कृषि विभाग द्वारा अनुदानित सुपर सीडर द्वारा गेहूं फसल की सीधी बुवाई हेतु कृषक कुलवंत सिंह के खेत में प्रदर्शन कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा किसानों को सुझाव दिया गया कि धान की फसल के बाद पराली को बिना जलाए ही सुपर सीडर के माध्यम से गेहूं की बुवाई की जाए, जिससे खेत में जैविक खाद मिलेगी तथा गेहूं की उपज अधिक प्राप्त होगी। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा को निर्देश दिए कि कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में सुपर सीडर अनुदान पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृषक कुलवंत सिंह ने सुपर सीडर से गेहूं बुवाई के फायदे बताते हुए कहा कि धान की कटाई के पश्चात पराली वाले खेत में बिना जुताई के सीधी बुवाई की जा रही है, जिससे कृषकों द्वारा पराली को बिना जलाए तथा कम कृषि क्रियाएं कर गेहूँ की उत्पादन लागत में कमी लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सुपर सीडर के मध्यम से प्रति हेक्टेयर (20 ली0 डीजल रू0 1800.00) में तथा कम समय में गेहूँ की बुवाई की जा सकती हैं।मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 40 से 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा, सहायक कृषि अधिकारी मोहम्मद यासीन, जगदीश त्यागी, दिनेश शर्मा, पवन कुमार आदि उपस्थित थे।

बिना फिटनेस दौड़ रहे थे विक्रम चलाने वालों पर लाइसेंस तक नहीं

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवम्बर , दून में नियमों का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक परिवहन से जुड़े वाहन संचालित हो रहे हैं। सोमवार को आरटीओ की टीम की चेकिंग में ऐसे मामले पकड़े गए। दुस्साहस ऐसा कि बिना लाइसेंस विक्रम चला रहे चालक ने तो आरटीओ की टीम को दौड़ा दिया।

आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी की अगुवाई में टीम ने सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में विक्रमों की चेकिंग को अभियान चलाया। इस दौरान परेड ग्राउंड के पास उन्होंने एक विक्रम चालक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह चकमा देकर भाग निकला। इसके बाद अधिकारी ने उसका पीछा किया और वाहन से करीब एक किलोमीटर आगे जाकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास लाइसेंस नहीं था। अधिकारी ने उसके खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई की। इसके अलावा टीम ने राजपुर रोड, परेड ग्राउंड, आईटी पार्क और अन्य क्षेत्रों में विक्रमों की चेकिंग की गई।

टीम ने 12 विक्रमों का चालान काटे और दो विक्रम वाहनों को सीज किया। ये दो विक्रम ऐसे थे, जिनकी फिटनेस नहीं थी। कुछ में ओवरलोडिंग पाई गई। आरटीओ ने महिला यात्रियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कई विक्रम चालक साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। सही जगह पर विक्रम नहीं रोकते, जिससे हादसे होने का डर बना रहता है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने विक्रम चालकों को निर्देश दिए कि वह नियमों का पालन करें। विक्रम में फायर इक्यूपमेंट और डस्टबिन लगाएं।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपनी ही रजिस्ट्री के खिलाफ दिए CBI जांच के आदेश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवंबर , उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने ही रजिस्ट्री कार्यालय के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मामला दिल्ली की अंगेलिया हाऊसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के देहरादून में स्थित करोड़ों मूल्य की भूमि से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अदालत में अंगेलिया कंपनी की इसी जमीन के प्रकरण को लेकर साल 2004 में एक मामला विचाराधीन था।

इसी दौरान प्रकाश में आया कि मामले को लेकर अदालत के एक फर्जी आदेश के जरिये कुछ लोगों ने दिल्ली की अदालत में लाभ लेने की कोशिश की। कंपनी के निदेशक संतोष बागला को जब इसका पता चला तो उन्होंने इस मामले की जानकारी एक पत्र के माध्यम से 2013 में न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से उत्तराखंड हाईकोर्ट को दी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वारेन घोष ने इस मामले में इन हाउस जांच के साथ ही तत्कालीन रजिस्ट्रार को पुलिस में अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए। नैनीताल के मल्लीताल स्थित कोतवाली में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। चूंकि मामला दिल्ली से जुड़ा था इसलिए पूरे प्रकरण को दिल्ली पुलिस को भेज दिया गया। लेकिन, दिल्ली पुलिस तब तक इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसको आपराधिक वाद में तब्दील कर दिया और 2013 में उच्च न्यायालय में इस मामले में आपराधिक याचिका दायर कर ली। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की पीठ में हुई। इसी बीच अंगेलिया हाऊसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक संतोष बागला ने प्रार्थना पत्र देकर अदालत से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। अदालत ने मामले में इसी साल अप्रैल में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंगेलिया कंपनी के अधिवक्ता आरपी नौटियाल और प्रशांत खन्ना ने बताया कि अदालत ने फैसला देने हुए अपनी ही रजिस्ट्री के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दिये हैं।

उत्तराखंड में इतने ज्यादा बाघ और गुलदार पकड़े गए कि रेस्क्यू सेंटर हो गए फुल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवम्बर , उत्तराखंड में गुलदारों और बाघों के लिए बनाए गए रेस्क्यू सेंटर फुल हो गए हैं। उनमें क्षमता से ज्यादा संख्या हो गई है। ऐसे में अब और जानवरों को रखने की जगह नहीं बची है। इससे वन विभाग चिंतित है। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को पत्र लिखकर जल्द नए रेस्क्यू सेंटर बनाने की अनुमति मांगी गई है।

राज्य में चिड़ियापुर (हरिद्वार), रानीबाग (हल्द्वानी), अल्मोड़ा और ढेला रेंज (कार्बेट पार्क) में चार रेस्क्यू सेंटर हैं। इनमें कहीं से भी रेस्क्यू किए गए गुलदार और बाघों को रखा जाता है, लेकिन वर्तमान में सभी क्षमता से ज्यादा भर चुके हैं। चिड़ियापुर में सात की क्षमता है, वहां 11 गुलदार रखे गए हैं। इनमें से दो अंधे, दो के पैर खराब हैं, जबकि बाकी आदमखोर हैं। जबकि, रानीबाग में दो की क्षमता है और वहां तीन गुलदार रखे गए हैं। इसी तरह अल्मोड़ा में दो की क्षमता है, वहां चार गुलदार रखे गए हैं।सूत्रों के अनुसार, विभाग की ओर से सीजेडए को पत्र लिखकर यहां से गुलदार अन्य राज्यों के सेंटरों में भेजने की मांग भी की जा चुकी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉ. समीर सिन्हा का कहना है कि गुलदारों की संख्या ज्यादा हो गई है, जो रेस्क्यू कर लाए जाते हैं वे तो कुछ समय बाद जंगल में छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन आदमखोर होने या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। दो और रेस्क्यू सेंटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उनके बनते ही सारी दिक्कत दूर हो जाएगी।

ढेला में बिना अनुमति रखे बाघ-गुलदार

कार्बेट पार्क में ढेला रेस्क्यू सेंटर में तीन बाघ और चार गुलदार रखे गए हैं। यहां अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी से फाइनल अनुमति के बिना ही रेस्क्यू सेंटर चल रहा है। फाइनल अनुमति के बाद ही इसके लिए क्षमता निर्धारण हो सकेगा। वहीं, चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर की भी अभी औपचारिक अनुमति नहीं है। रेंजर ढेला संदीप गिरि का कहना है कि ढेला रेस्क्यू सेंटर की अनुमति का प्रोसेस चल रहा है। बस फाइनल अनुमति मिलनी है। सारी औपचारिकताएं पूरी कर सीजेडए को भेजी गईं हैं।

दो शावकों को दून जू में रखने की मांग

चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर में दो गुलदार के शावक भी हैं, जो चार-पांच महीने के हैं। काफी समय से रहने के कारण इन्हें मनुष्यों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इस कारण वे अब जंगल में नहीं रह सकते। ऐसे में उन्हें देहरादून जू में रखने की मांग हरिद्वार वन प्रभाग की ओर से चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन से की गई है। रेस्क्यू सेंटर में उन्हें ज्यादा दिन रखने की जगह नहीं है।

सावधान ! कोरोना से भी खतरनाक वायरस बना रहा चीन

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवम्बर , दुनिया अभी कोरोना वायरस के संकट से उबरी भी नहीं है और एक खबर ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन और पाकिस्तान मिलकर रावलपिंडी के एक रिसर्च लैब में कोरोना से भी घातक वायरस तैयार कर रहे हैं। कोरोना वायरस 2019 में चीन के वुहान से ही दुनिया भर में फैला था।मीडिया रिपोर्ट्स में आइये जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान पर है कौन से वायरस बनाने का आरोप? ये वायरस है कितना घातक? क्यों इन्हें कहा जा रहा बायोलॉजिक वेपन?

चीन पाकिस्तान की लैब में बना रहा कोरोना से भी घातक वायरस

चीन और पाकिस्तान पर आरोप है कि दोनों मिलकर एक घातक वायरस को डेवलप कर रहे हैं। वायरस के रूप में इस बायोवेपन पर रिसर्च पाकिस्तान के रावलपिंडी स्थित एक रिसर्च सेंटर में चल रही है।जियो-पॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक, घातक वायरस को बनाने के लिए चीन की कुख्यात वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और पाकिस्तानी सेना के डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन यानी DESTO ने एक बहुत ही एडवांस साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है।इस लैब की लोकेशन को कड़ाई से छिपाकर रखा गया है। कई ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन पाकिस्तान में ऐसे वायरस बना रहा है, जिसमें कोरोना की तुलना में कहीं बड़े पैमाने पर फैलने और बीमारी पैदा करने की क्षमता है।

पहाड़ के विधायकों ने अधिक निधि की उठाई मांग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के दो जिले हरिद्वार और यूएसनगर मैदान क्षेत्र में आते हैं, जबकि देहरादून और नैनीताल का कुछ हिस्सा पहाड़ तो कुछ मैदान में आता है. लेकिन शेष नौ जिले पूरी तरह से पहाड़ क्षेत्र में आते हैं. मोटे तौर पर करीब विधानसभा की 35 सीटें पहाड़ में तो 35 सीटें मैदान में आती हैं. पहाड़ के विधायकों का कहना है कि पहाड़ में विधानसभाओं का क्षेत्रफल मैदानी क्षेत्र की विधानसभाओं की अपेक्षा कहीं अधिक है. लिहाजा, पहाड़ में क्षेत्रफल के आधार पर विधायक निधि और बजट का आंवदन होना चाहिए.कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया और लैंसडौन के एमएलए दिलीप रावत भी मानते हैं कि पहाड़ में क्षेत्रफल तो अधिक है ही विकास कार्यों में लागत भी अधिक आती है. धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि बजट आंवटन की पूरी प्रकिया में ही समीक्षा की जरूरत है. इसे टॉप हिल्स, फुट हिल्स और मैदानी क्षेत्रों के आधार पर बांटा जाना चाहिए.बता दें कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में विधायकों को विधायक निधि के रूप में एक वित्तीय वर्ष के लिए तीन करोड़ 75 लाख का बजट मिलता है, जबकि हिमाचल में यही राशि एक करोड़ अस्सी लाख के आसपास है.पड़ोसी राज्य यूपी में सालाना पांच करोड़ की विधायक निधि दी जाती है.उत्तराखंड में विधायकों की ताजा मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी.

एसएसपी पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने अधीनस्थों को दिये कड़े दिशा-निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी गढ़वाल , 15 नवम्बर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल श्वेता चौबे ने अब पौड़ी में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नए चार्ज के कुछ ही दिन बाद अब महकमे के अधिकारीयों को मैडम की शार्प पुलिसिंग और जन सरोकार की प्राथमिकता का अजेंडा भी दिखने लगा है। इसी कड़ी में एसएसपी श्वेता चौबे ने जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को अपने-अपने सर्किल एवं थाना क्षेत्रान्तर्गत निम्न कड़े दिशा निर्देशदिए हैं। आइये जानते हैं वो सख्त निर्देश क्या है जिसके आधार पर पौड़ी गढ़वाल में आईपीएस श्वेता चबे द्वारा मित्र पुलिस की तस्वीर का खाका खींचा जा रहा है।

1. विक्टिम ऑरिएन्टेड पुलिसिंगः- थाने पर आने वाले प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की समस्या को अवश्य सुना जाये और उसके निस्तारण के भरसक प्रयास किये जायें तथा समस्या के निराकरण के बाद पीड़ित से फीडबैक अवश्य लिया जाय। थाने पर गठित महिला हैल्प डेस्क हर हाल में क्रियाशील रहे व महिलाओं की समस्याओं को गम्भीरता से सुना जाये।मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा "गौरा शक्ति एप" में जोड़े गये "POSH Act" के लिंक के तहत सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान, होटल/धर्मशाला/रिजॉर्ट इत्यादि में कार्यरत महिलाओं द्वारा स्व पंजीकरण कराया जाता है तो 15 दिन में उसका हाल-समाचार पूछते हुये उनकी सुरक्षा की जाये।

2. नशाः- मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अपेक्षानुसार वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को नशा मुक्त बनाया जाना है। अतः अवैध शराब व ड्रग्स (चरस, अफीम, स्मैक आदि) की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु इन्हें बेचने व सप्लाई करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आबकारी अधिनियम व एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर कार्यवाही की जाये।

3. निरोधात्मक कार्यवाहीः- वर्तमान में प्रोफेसनल पुलिसिंग धीरे-धीरे समाप्त हो चुकी है। जिस कारण प्रभावी पुलिसिंग के लिये SSP श्वेता चौबे ने जनपद में अवैध शराब की बिक्री, जुआ-सट्टा का कारोबार, अवैध हतियारों की सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा अधिनियम, 110 जी दंप्रसं0 के तहत कार्यवाही करते हुये अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति को कुर्क करते हुये जिला बदर की कार्यवाही करने, वांछित, मफरूर एवं ईनामी अपराधियों की गिरफ्तारी किये जाने के कड़े निर्देश जनपद में आगमन पर दिये गये थे।

4. यातायातः- जनपद की कोतवाली पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार व लक्ष्मणझूला में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त किया जाये। ट्रैफिक पुलिस के अलावा थाना प्रभारी स्वंय यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये जिम्मेदार होगें। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नियमित रूप से वाहन चैकिंग करते हुये बिना हेलमेट, ओवरस्पीड, ओवरलोड़ वाहनों, दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी ले जाने व शराब पीकर वाहन चलाने वालों की विषेश रूप से चैकिंग करते हुये इनके विरूद्ध *मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर डी0एल0 निलम्बन की कार्यवाही भी की जाये। थाना क्षेत्रों में दुर्घटना सम्भावित स्थलों को चिन्हित कर इन स्थानों पर साईन बोर्ड लगाये जायें तथा इन स्थानों पर सुधारीकरण की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय कर सुधारीकरण की कार्यवाही करायी जाये।

5. रात्रि गश्तः- सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में प्रभावी रात्रि गश्त सुनिश्चित करें व स्वंय रात्रि गश्त को ब्रीफ कर रवाना किया जाये। श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी रात्रि में एक बार अवश्य गश्त को चैक करें व उसकी फोटोग्राफ रात्रि चैकिंग ग्रुप में अवश्य डालें।

दिव्य प्रेम सेवा मिशन कार्यक्रम में धामी सरकार ने गिनाई उपलब्धियां

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हरिद्वार , 15 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौआबाद श्यामपुर, हरिद्वार में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए दिव्य प्रेम सेवा मिशन के सेवा प्रकल्पों के अंतर्गत बने डिवाइन कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के प्रथम चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने भवन निर्माण में अपना अहम योगदान देने वाले लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारें में जितना भी कहा जाए, उतना कम है। उन्होंने कहा मुझे छात्रकाल से ही दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष आशीष का दिव्य सानिध्य प्राप्त होता रहा है। समाज को शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करने का जो संकल्प आशीष ने लिया है, उसी का परिणाम है कि आज हम इस विशिष्ट संस्थान को इस स्वरूप में देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा आशीष समाज सेवा के कार्यों में समर्पण के कार्य को बड़ा रहे है। चिकित्सा-शिक्षा क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद हैल्थ मिशन के तत्वावधान में उत्तराखंड के युवाओं को शिक्षित करने का जो बेड़ा दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने आरंभ किया है उसके लिए देवभूमि की समस्त जनता इस मिशन से जुड़े हुए प्रत्येक स्वयंसेवक की आभारी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मेरा यह प्रयास रहता है कि हमारी सरकार शिक्षा एवं स्वास्थ, के क्षेत्रों में कार्य कर रहे किसी भी संस्थान की हर संभव सहायता कर सकें। उन्होंने कहा केंद्र सरकार के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई योजनाओं का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा हमारी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब युवा उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, तब तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। इस विकल्प रहित संकल्प की सिद्धि के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में हमारी सहायता करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम की पावन भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बताया था, इस बार चार धाम यात्रा के दौरान 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की, मां गंगा एवं बाबा केदार के आशीर्वाद से यात्रा सुगम एवं सुरक्षित रही। उन्होंने कहा आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा जैसे हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन हो रहा है, आज भारत विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की सांस्कृतिक चेतना के पुनरोत्थान का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम सभी देवभूमि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री के विशेष लगाव से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने कहा हवाई कनेक्टिविटी, रेल, सड़क हर क्षेत्र में कार्य तीव्र गति से हो रहा है। आज ऋषिकेश एम्स के माध्यम से उत्तराखंड में हम विधार्थियों को न केवल उत्कृष्ट चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध करा पा रहे हैं बल्कि लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करने में सक्षम हुए हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री धामी के कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई बड़े एवं ऐतिहासिक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रदेशवासी को मुफ्त में इलाज देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक राज्य के अंदर 50 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बन गए हैं एवं 6 लाख से अधिक मरीजों का मुक्त में ईलाज करवाया जा चुका है। उन्होंने कहा गर्भवती महिलाओं के चेकअप एवं बच्चे को जन्म देने के बाद उन्हें घर तक गाड़ी मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक जिले में डायलिसिस का इलाज मुफ्त में किए जाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा संपूर्ण देश में सबसे सस्ती मेडिकल शिक्षा हमारे राज्य में है।

आचार्या बाल कृष्ण ने कहा कि दिव्य प्रेम सेवा मिशन का मकसद समाज की सेवा है। उन्होंने कहा सेवा के कार्य हेतु मनुष्य को साधना की आवश्यकता होती है उन्होंने कहा तप और साधना से ही विकास संभव है, सामाजिक कार्य कर आमजन के विकास से ही समाजसेवा संभव है। उन्होंने कहा दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं।इस अवसर पर डॉ. आशीष गौतम (अध्यक्ष दिव्य प्रेम सेवा मिशन), डॉ. कृष्ण गोपाल (सह सरकार्यवाह आरएसएस), योग गुरु स्वामी रामदेव, केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे (भारी उद्योग, भारत सरकार), भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, आके श्रीवास्तव (अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक ओ.एन.जी.सी), पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रसाद शुक्ल, विधायक प्रदीप बत्रा, विधायक आदेश चौहान एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

काम की बात : ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो क्या करना चाहिए ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

लोग अक्सर ट्रेन में सफर के दौरान ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं जहाँ उनका लगेज , कीमती सामान , पर्स , मोबाइल आदि चोरी हो जाता है। जानकारी के अभाव में यात्री मन मार कर रह जाते हैं लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह से शिकायत कर अपना सामान वापस पा सकते हैं। एक्सपर्ट्स से जानिए कुछ अहम सवालों के जवाब -

सवाल- चलती ट्रेन में आपका यानी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाए तो क्या करें ?

जवाब- चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो पैसेंजर ट्रेन के टीटी, कंडक्टर, कोच अटेनडेंट, गार्ड RPF या GRP एस्कॉर्ट को इस बात की जानकारी दें। वो आपके चोरी हुए या गुम हुए सामान की शिकायत करने में मदद करेंगे।

सवाल- ट्रेन में पैसेंजर का सामान चोरी होने वाले मामले पर कौन एक्शन ले सकता है, RPF या GRP ?

जवाब- GRP, जी हां। GRP पुलिस के पास ही इंडियन पैनल कोड के मामलों पर एक्शन लेने की पावर है। आप चलती ट्रेन में RPF या टीटी से FIR फॉर्म लेकर शिकायत जरूर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन RPF भी आपका केस GRP पुलिस को ही हैंडओवर करेगी। RPF के पास रेलवे की प्रॉपर्टी चोरी होने पर एक्शन लेने की पावर है। जैसे- ट्रेन के पर्दे, तकिए या कम्बल।

सवाल- ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो FIR के लिए पैसेंजर को अपनी यात्रा ब्रेक कर किसी स्टेशन पर उतरना जरूरी है ?

जवाब- नहीं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप चलती ट्रेन में भी FIR दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हो और पैसेंजर की गवाही की जरूरत हो, तब आपको किसी स्टेशन पर उतरकर GRP थाने में गवाही देनी पड़ सकती है।

उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। न्यूज़ वायरस हिंदी दैनिक का मकसद है अपने पाठकों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हो रहे बदलाव , उनके अधिकार और विभिन्न योजनाओं की मुक्कमल सुचना दी जा सके।

बधाई हो! दुनिया में आ गयी 8 अरबवीं बिटिया

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवंबर , दुनिया की आबादी आठ अरब पार कर गई. भले ही बढ़ती जनसंख्या चिंता का कारण हो मगर लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार 8 अरबवां बच्चा है कौन? लोग सर्च कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि किसी देश में आठ अरबवें बच्चे ने जन्म लिया है. अगर आप कयास लगा रहे हों कि ये बच्चा भारत, चीन, अमेरिका या ब्रिटेन में हुआ तो आप गलत हैं. सही जवाब में है फिलीपींस की राजधानी मनीला. दावा किया जा रहा है कि मनीला में बेबी गर्ल ने आज सुबह जन्म लिया है और वो ही 8 billionth बच्ची है. संयुक्त राष्ट्र ने पहले अनुमान लगाया था कि इस साल नवंबर के मध्य तक वैश्विक मानव आबादी आठ अरब तक पहुंच जाएगी. उनका ये पूर्वानुमान बिल्कुल सही निकला. नवजात का नाम विनिस माबनसाग रखा गया है. उसकी मां मारिया मार्गरेट विलोरेंट बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को दुनिया का 8 अरबवां बच्चा माना गया है. मेरे लिए ये आशीर्वाद जैसा है. जनसंख्या और विकास आयोग (POPCOM) के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लिनेथ थेरेसी मोनसाल्वे ने कहा कि वे उम्मीद कर रहे हैं कि विनिस भविष्य में विकास का रोल मॉडल बनेंगी.

डॉक्टर ने किया 2 घंटे तक इंतजार

अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रोमियो बिटुइन ने कहा कि तो हमने अभी फिलीपींस में दुनिया के 8वें अरब बच्चे को देखा है. इसलिए हमने रात 11 बजे से करीब दो घंटे तक इंतजार किया. बीती रात नॉर्मल डिलीवरी से करीब 01 बजकर 29 मिनट में बच्ची का जन्म हुआ. POPCOM के अनुसार फिलीपींस में जनसंख्या 2022 में 1.9 प्रजनन दर के साथ धीमी गति से बढ़ रही है. इसका मतलब है कि एक मां केवल दो से कम बच्चों को जन्म देती है. यह 2017 में 2.7 प्रजनन दर की तुलना में कम है.

सर्दियों में सुबह पिए गर्म पानी तो मिलेंगे ये फायदे

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 15 नवंबर , पानी जीवन की मूलभूत जरूरत है और किसी भी जीवित प्राणी के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। मानव शरीर का लगभग 70 प्रतिशत पानी से बना है, इसलिए फिट रहने के लिए सही मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।

माना जाता है कि अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं, तो आपको सुबह उठकर सबसे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। कुछ लोगो को तो यहां तक कहना हैं कि बिस्तर से बाहर निकलने के तुरंत बाद पानी पीने से तेजी से वेट लॉस में हेल्प मिलती है, जबकि दूसरों को लगता है कि इससे आपको मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में अक्सर लोग पानी पीना कम कर देते हैं और सुबह के समय तो पानी पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन गर्मियों की तरह सर्दियों के सुस्त दिनों में भी वजन कम करने और खुद को पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहने के लिए सुबह खाली पेट पानी पीना बेहद जरूरी होता है। मेरा यह मानना है कि दिन की तुलना में सुबह के समय खाली पेट पानी पीने से आपको ये 3 फायदे हो सकते हैं।

यह सच है कि पानी पीने से कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि यह आपको भरे हुए का अहसास कराता है। वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों को अक्सर पानी का सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है ताकि ओवरईटिंग को रोका जा सके। माना जाता है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से पूरे दिन ली जाने वाली कैलोरी की मात्रा कम करने में हेल्प मिलती है साथ ही यह आपको हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करता है।

सुबह पानी पीने से वास्तव में हम हाइड्रेट होते है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह का यूरीन आमतौर पर गहरे पीले रंग का होता है। वास्तव में, यूरिन हाइड्रोजन लेवल का एक स्पष्ट संकेत नहीं है। यह आमतौर पर सुबह के समय डार्क होता है क्योंकि यह अधिक फोकस होता है क्योंकि आपने रात भर पानी नहीं पिया होता है। इसलिए सुबह के समय पानी पीने से हमें रिहाइड्रेट होने में मदद मिलती है।

कब्ज से परेशान महिलाओं के लिए सुबह गर्म पानी पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये पीरियड्स के दिनों में होने वाले ऐंठन और दर्द को दूर करने में हेल्प करता है। बदलते मौसम में होने वाली गले की खराश को दूर करता है।"

गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में डूबने से मुरादाबाद के दो युवकों की मौत, एक की होने वाली थी शादी

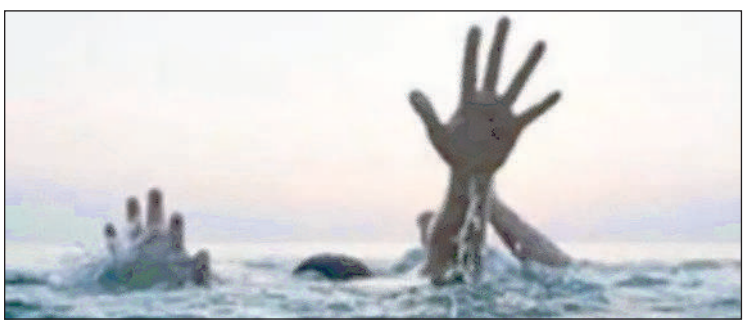

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रामनगर (नैनीताल) 15 नवंबर। गर्जिया मंदिर के पास कोसी नदी में नहाने गए मुरादाबाद के दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रख दिया है। गौरव भाटिया (30) पुत्र इंदर भाटिया और अतुल कुमार (29) पुत्र महेश कुमार निवासी फेज दो आशियाना कॉलोनी मुरादाबाद मंगलवार दोपहर आई-20 कार से गर्जिया पहुंचे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों युवक गर्जिया मंदिर के पीछे बने गहरे कुंड में नहा रहे थे। कई लोगों ने उन्हें गहरे कुंड में जाने से रोका था लेकिन वह नहीं माने। दोपहर करीब तीन बजे के दोनों गहरे कुंड में डूब गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने गहरे कुंड से दोनों युवकों के शवों को बाहर निकाला। गर्जिया चौकी प्रभारी कश्मीर सिंह ने बताया कि दोनों युवकों की कार से मिले मोबाइल से उनकी पहचान हुई। दोनों युवकों के शव रामनगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। रामनगर अस्पताल पहुंचे अतुल कुमार के परिजनों ने कि बताया कि दोनों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। अतुल की फरवरी में शादी होनी थी। सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि बुधवार को दोनों के शवों को पोस्टमार्टम किया जाएगा।

संपादकीय

समूची धरती के अस्तित्व को खतरा

मिस्र जलवायु सम्मेलन में भारत ने सभी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को धीरे-धीरे कम करने पर सहमति बनाने का आह्वान किया है. अभी तक मुख्य रूप से कोयले पर वैश्विक निर्भरता घटाने और अंततः समाप्त करने पर जोर दिया जाता रहा है. लेकिन पेट्रोलियम पदार्थ भी ग्रीनहाउस गैसों के भारी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं. इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों ने जलवायु वार्ता के अध्यक्ष तथा सम्मेलन के मेजबान मिस्र से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि सम्मेलन के संकल्प पत्र में हर तरह के जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल को रोकने के प्रयास करने संबंधी प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए. भारत ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बहुत हद तक कोयले पर निर्भर है. हालांकि देश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं तथा दुनियाभर में इसकी सराहना भी हो रही है, परंतु कोयले से जल्दी छुटकारा पाना संभव नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में हुए पिछले सम्मेलन में कहा भी था कि भारत 2070 तक अपने उत्सर्जन को शून्य के स्तर पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है. भारत और फ्रांस के साझा नेतृत्व में चल रहे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में सौ से अधिक देश शामिल हो चुके हैं. विभिन्न बहुपक्षीय समूहों में भी भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर सहकार बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता रहा है. इसके बावजूद कोयले के उपयोग को लेकर भारत की आलोचना होती है, जबकि बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले देश भी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं. यदि सम्मेलन में जीवाश्म ईंधनों को लेकर आम राय बनती है, तो हर स्तर पर उत्सर्जन घटाने की कोशिशें तेज होंगी. जलवायु परिवर्तन एक देश की समस्या नहीं है, उससे समूची धरती के अस्तित्व को खतरा है. इसलिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिए हर स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए. आशंका है कि पेट्रोलियम ईंधन पर आश्रित देश भारत के प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं. इनमें कई विकासशील देश भी हो सकते हैं. भारत, चीन, सऊदी अरब समेत विकासशील देशों का समूह अनेक जलवायु मुद्दों पर विकसित देशों पर साझा दबाव बनाने में सफल रहा है. आशा है कि ये देश भारत के पक्ष को सकारात्मक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे. संयुक्त राष्ट्र जलवायु समिति भी सभी जीवाश्म ईंधनों को समयबद्ध तरीके से हटाने की सिफारिश कर चुकी है. यदि जीवाश्म ईंधनों तथा आपदाओं की क्षतिपूर्ति को लेकर इस सम्मेलन में सहमति नहीं बनती है, तो अभी किये जा रहे उपायों को बड़ा झटका लगेगा. व्यापक वैश्विक सहयोग से ही जलवायु संकट का निवारण हो सकता है.

जेल वार्डर की बंपर भर्ती, 12वीं पास करें अप्लाई और पाएं 69000 तक सैलरी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

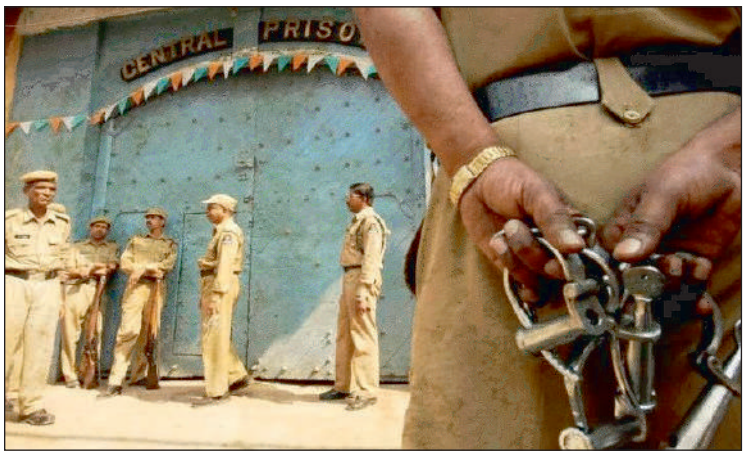

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, UKPSC ने जेल वार्डर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं. भर्ती के माध्यम से राज्य के विभिन्न जेलों में पुरुष एवं महिला जेल वार्डर के पद भरे जाएंगे. भर्ता के लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाकर 5 दिसंबर 2022 तक अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं.कुल 238 वैकेंसी भर्ती के तहत भरी जानी हैं. जिनमें 214 पद पुरुष के एवं 24 पद महिलाओं के लिए हैं. पदों पर उम्मीदवारों का चयन शारीरिक पात्रता एवं लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. शारीरिक पात्रता परीक्षा पहले होगी, जिनमें सफल उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक परीक्षा में पुरुष उम्मीदवारों को बाल थ्रो, चिन्हअप, लंबी कूद, दंड बैठक और दौड़ जैसी स्पर्धाओं में हिस्सा लेना होगा. वहीं महिला उम्मीदवारों को दौड़ एवं चिन्हअप में भाग लेना होगा.बता दें कि शारीरिक परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें सफल होने के लिए कैंडिडेट्स को हर स्पर्धा में कम से कम 50 फीसदी अंक लाने होंगे. शारीरिक मानदंड की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम उंचाई 165 सेमी होनी चाहिए. हांलाकि पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह 160 सेमी है. वहीं न्यूनतम वजन 55 किलो होना चाहिए.भर्ती के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार की आयु 21 से 35 वर्ष के बाच होनी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को 21700 से लेकर 69100 रुपए का वेतनमान दिया जाएगा. भर्ता संबंधी अन्य जानकारी के लिए उम्मादवार इस लिंकhttps://ukpsc.net.in/JailGaurd22LV1/docs/Bandirakshak%20_Advertisement_22.pdf पर विजिट कर नोटिफिकेशन चेक करें.

गांव का विकास करने के में जीपीडीपी का महत्वपूर्ण योगदान : युगल किशोर पन्त डीएम, यूएस नगर

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रूद्रपुर 15 नवम्बर , जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त की अध्यक्षता में सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु महत्वपूर्ण बैठक डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में सम्पन्न हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निर्धारित 09 विषयों तथा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) क्षेत्र पंचायत विकास योजना (बीपीडीपी) एवं जिला पंचायत विकास योजना (जेडपीडीपी) निर्माण के सम्बन्ध में रेखीय विभागों के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गांव का विकास करने के में जीपीडीपी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जीपीडीपी तैयार करने में गांव के विकास संबंधी सभी पहलुओं को ध्यान में रखें। ग्राम पंचायत को अधिक सशक्त बनाने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को लागू किया गया है।उन्होंने कहा कि जीपीडीपी के अंतर्गत सभी 29 विषयों को कार्यान्वित करने वाले सभी विभाग अपने फ्रंट लाइन वर्कर के माध्यम से सभी योजनाओं का निर्धारण ग्रामसभा के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी योजनाओं को मिलाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों में जनता की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य, सहित सभी रेखीय विभागों के कार्मिकों द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठकों में अवश्य प्रतिभाग किया जाये। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही योजनाओं की सम्पूर्ण डिटेल सम्बन्धित क्षेत्रों के ग्राम प्रधानों को भी मुहैया कराई जाये। उन्होंने सड़क निर्माण, जल जीवन मिशन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही बड़ी योजनाओं में ग्राम पंचायतों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के निर्देश पंचायतीराज विभाग को दिये। उन्होंने ग्राम सभा की खुली बैठकों में वेस्ट मैनेजमेंट हेतु बायलोज पास कराने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड धारकों की पात्रता पर चर्चा कराने के भी निर्देश पंचायतीराज विभाग को दिये। बैठक में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, जिला पंचायतराज अधिकारी आरसी त्रिपाठी, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिमवाल, मुख्य कृषि अधिकारी एके वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

दैनिक
न्यूज वायरस
न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।
सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002
email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094
वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा

अतिथि शिक्षकों के 2300 पद शीघ्र भरे जाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 15 नवम्बर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिथि शिक्षकों के 2300 पद शीघ्र भरे जाएं। हर जनपद में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना तथा विद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के 03 हजार रिक्त पद भरने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों अविलंब मरम्मत की जाए। राज्य के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र-छात्राओं को आने वाले शैक्षणिक सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाए। कक्षा 1 से 8 वीं तक पहले से ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार के लिए आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारी भी समय-समय पर स्कूलों की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नियमित स्कूलों में जाकर पठन-पाठन एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शीघ्र नियुक्ति दी जाए। अध्यापकों के मेडिकल एवं अध्यापिकाओं के मेडिकल, मैटरनिटी लीव एवं चाइल्ड केयर लीव के दौरान कक्षाएं बाधित न हो, इसके लिए स्कूलों में पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाए। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं, उनके जल्द ही आयोग को अधियाचन भेजे जाए। बीआरपी एवं सीआरपी के रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षकों का मेडिकल रिम्बरसमेंट एवं सेवानिवृत्त होने के बाद जीपीएफ भुगतान समय पर हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा की बीआरपी एवं सीआरपी के रिक्त 950 पद शीघ्र भरे जाएं। शिक्षा व्यवस्था की गतिविधियां एवं ट्रांसफर की व्यवस्था ऑनलाइन की जाय।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयों की परफोर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) स्कोर से संबंधित यूडाइस पोर्टल में सभी डाटा अपडेट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर सख्त कारवाई भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं, इन्हें जल्द भरना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि वे नियमित स्कूलों का निरीक्षण करें। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम्, रविनाथ रमन, एस.एन. पाण्डेय, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव योगेन्द्र यादव एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

29 नवंबर से पांच दिसंबर तक दून में होगा विधानसभा शीतकालीन सत्र, राज्यपाल ने दी मंजूरी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवंबर। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से देहरादून में ही होगा। मंगलवार को राज्यपाल ले. जन. (सेनि) गुरमीत सिंह ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश की पांचवीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक की अवधि का प्रस्ताव तैयार किया है। विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम चंद्र पंत के मुताबिक, राज्यपाल ने देहरादून विधानभवन में सत्र के आयोजन की अनुमति दी है। इसी हिसाब से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं।

बदली परिस्थितियों में होने जा रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कानून व्यवस्था, वनंतरा रिसार्ट प्रकरण, भर्ती घोटाले जैसे तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है। सरकार भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए अपने तरकश में तीर तैयार कर रही है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करेगी। इसके अलावा कई विधेयक भी सरकार पारित करा सकती है। यद्यपि, विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद ही सत्र के कामकाज को लेकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

अलग-अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल

विधानसभा सत्र के लिए विधायकों ने अलग-अलग विभागों के 500 से अधिक सवाल लगाए हैं। एक-दो दिन में इनकी संख्या और बढ़ सकती है।

'गोल्डन ब्वाय' लक्ष्य सेन को मिलेगा अर्जुन अवॉर्ड, राष्ट्रमंडल खेलों में हासिल की थी स्वर्णिम जीत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 15 नवंबर। उत्तराखंड के गोल्डन ब्वाय शटलर लक्ष्य सेन को प्रतिष्ठित अर्जुन अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने यह अवॉर्ड अपने दादा को समर्पित किया है। इसकी जानकारी लक्ष्य ने अपने ट्वीटर एकाउंट पर साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किए जाने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह ऐसा संयोग है कि इन पुरस्कारों की घोषणा 14 नवंबर को की जाती है, ठीक उसी दिन जब मेरे प्यारे दादा स्वर्गीय श्री सी.एल. सेन 2013 में हमें छोड़कर चले गए थे। दादाजी, यह आपके लिए है '

बता दें कि हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन बैडमिंटन के एकल मुकाबले के फाइनल में लक्ष्य सेन ने मलयेशिया के त्जे यंग को तीन गेम तक चले मुकाबले में एक के मुकाबले दो सेट से शिकस्त देकर स्वर्णिम कामयाबी हासिल की थी। सीएम धामी ने भी उन्हें इसके लिए बधाई दी थी।

लक्ष्य सेन ने बचपन से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। बचपन में पिता व कोच डीके सेन चार बजे स्टेडियम निकल जाते थे, जबकि मां शिक्षिका थीं। ऐसे में तीन साल की उम्र में पिता ने लक्ष्य को एकेडमी ले जाना शुरू किया।

वहां एक बार जो लक्ष्य ने रैकेट पकड़ा, इसके बाद बचपन के खेलकूद सब भूल गया। डीके सेन के पारिवारिक मित्र और उनसे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले गोकुल सिंह मेहता का कहना है कि बचपन में लक्ष्य को रिमोट कार बहुत पसंद थी।

मम्मी के सामने जब भी वह होता तो रिमोट वाली कार चलाता था, लेकिन पापा डीके सेन के घर आने की आहट होते ही उसे छिपा देता था। धीरे-धीरे स्टेडियम में जब मेहनत ज्यादा पड़ने लगी तो उसने बचपन के खेल और अपनी प्यारी रिमोट कार भी छोड़ दी और बैडमिंटन में अपना करियर बनाया।

लक्ष्य सेन की प्रमुख उपलब्धियां

- विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 स्पेन - कांस्य पदक।
- ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इंग्लैंड - रजत पदक।
- इंडिया इंटरनेशनल सुपर सीरीज 2022 दिल्ली - स्वर्ण पदक।
- पोलिश ओपन 2019- रजत पदक।
- योनेक्स बेल्जियम इंटरनेशनल 2019 - स्वर्ण पदक।
- योनेक्स डच ओपन 2019 - स्वर्ण पदक।
- सारलोलकस ओपन 2019 सारबरूकेन - स्वर्ण पदक।
- स्कॉटिश ओपन ग्लासगो 2019 - स्वर्ण पदक।
- बांग्लादेश इंटरनेशनल चैलेंज 2019 - स्वर्ण पदक।
- योनेक्स डच ओपन 2021 - रजत पदक।
- विक्टर डेनमार्क ओपन 2021 - कांस्य पदक।